

[Shri Suresh Kalmadi]

unately due to the poor service conditions and unattractive salaries, they seek greener pastures of the private sector. I would like to warn the Government that if the service conditions and pay and allowances of the armed forces are not improved immediately, it will have an impact on the performance of these brave men in future wars.

And before I end, I would like to point out a very grave matter. Last week, the Chief of the Army Staff, Gen. Krishna Rao, announced in Bombay that there would be further increase in the pay and allowances of the armed forces personnel. This is after the Republic Day announcement. I do not know how the Army Chief made the announcement which is a prerogative of the Defence Minister. I hope the Defence Minister is going to confirm the announcement made by the Army Chief. Otherwise, it will lead to demoralisation in the armed forces.

REFERENCE TO THE REPORTED ACUTE WATER AND FOOD SHORT-AGE IN MAHARASHTRA

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): I draw attention to the grave situation in my State, Maharashtra, regarding the drought and particularly to the aspect of drinking water in the villages. About 17,000 villages are the affected villages which are in the grave zone of getting no water. Sir, the Maharashtra State has totally demanded about Rs. 131 crores as credit component and non-credit component from the Central Government. Against that the Central Government has sanctioned a pitiful assistance of Rs. 56.38 crores.

Then, Sir, the requirement for drinking water is roughly about Rs. 27.41 crores, to supply water by bullock-carts to these villages. Sir, even for this purpose the Central Government has granted Rs. 5 crores. So, this is the position as regard drinking water in the Maharashtra State. And the Maharashtra Chief Minister is expected to be in Delhi

in a day or two to plead with the Central Government for massive assistance for the drought-prone areas scheme.

Another aspect of it is the supply of rice to the Maharashtra State. Its quota was 75,000 tonnes per three months, and it has been slashed to 25,000 tonnes. So, in respect of the administration of drinking water on the one side and food on the other side, Maharashtra has been worst affected. I request you and through you the Government that on both these counts massive assistance should forthcome and the new Chief Minister should be given this assistance so that he can be of help to the people.

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): I support the proposal, Sir.

PERSONAL EXPLANATION BY SHRI ASAD MADNI

श्री असद मदनी : (उत्तर प्रदेश) :
जनाबे सदर, हमारे मुल्क के दस्तूर ने मुल्क के तमाम बसने वालों को मजहब पर चलने की पूरी आजादी दी है और अपनी खुशी से जो चाहे अपने मजहब पर चल सकता है और इसमें उसे कोई दिक्कत नहीं है । लेकिन कल हमारे मेम्बर श्री रामेश्वर सिंह जी ने यहाँ पर यह इल्जाम लगाया—कल की जो कार्यवाही है उसके पेज 531 पर यह बात मौजूद है—उसमें उन्होंने यह बात कही थी मेरे मुताल्लिक कि असद मदनी ने जामा मस्जिद में बैठ कर हरिजनों का धर्म परिवर्तन अपने हाथों से करवाया है और इसी तरह से यह भी कहा था कि अगर मैं यह कह रहा हूँ, अगर तुम इस बात को गलत कहते हो तो तुम्हारे कहने से यह बात गलत थोड़े हो जायेगी । मेरे पास फोटो मौजूद हैं और मैं कल फोटो लेकर आऊंगा और अगर यह बात असत्य हो जायेगी तो मैं इस सदन से अपना इस्तीफा दे कर हमेशा-हमेशा के लिये बाहर चला जाऊंगा ।

में समझता था कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसको वह पूरी सच्चाई से यहां साबित करेंगे और फोटो दिखायेंगे। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात वह कहते थे लेकिन पता नहीं कहां का वाक्या है। मैंने तो आज तक इस त्रिस्म की किसी कार्यवाही में शिरकत नहीं की और जामा मस्जिद की किसी मीटिंग में तो मैं साल-डेढ़ साल से शरीक भी नहीं हुआ। बिल्कुल झूठी बात उन्होंने कही है और इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं और कहते हैं कि सही साबित न कर सके तो इस्तीफा दे देंगे। आज वह तारीख मुकर्रर कर के गये थे। आज उन को आना चाहिए था। जब उनका इतना असरार है अपनी बात पर तो उसको उसे साबित करना चाहिए। लेकिन आज वह हैं नहीं और आप उनको रिटायर नहीं कर सकते। तो इस मामले को आप प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द कर दीजिए, ताकि वह देखें और इस मामले में अगर उनके पास कोई सबूत हों तो हम भी उसकी सफाई दें। होम मिनिस्ट्री अगर इसके सबूत दे तो वह भी देखें। मेरी यह दरखवास्त है कि प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द इसे कर दिया जाए ताकि कम से कम मेम्बर जो यहां कीचड़ उछालते हैं छोटी-छोटी बात कह कर, वह न कर सकें।

श्री उपसभापति : आप नोटिस लिख कर भेज दीजिए।

श्री असद मवनी : बहुत अच्छा।

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 28TH FEBRUARY, 1983.

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाय राय) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 28 फरवरी, 1983 से प्रारम्भ होने

वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा:

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर आगे चर्चा।
2. वर्ष 1983-84 के लिये रेल बजट पर सामान्य चर्चा।

जैसाकि सदस्यों को विदित ही है कि वर्ष 1983-84 के लिये सामान्य बजट सोमवार, 28 फरवरी, 1983 को सायं 6.30 बजे सभा पटल पर रखा जाएगा।

श्री शिव चन्द्र झा (बिहार) : यह अगले सप्ताह की कार्रवाई के बारे में है न। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि यहां उठ चुका है "नो-डे-यट-नेम्ड" कभी नहीं लिखा जाएगा। इस प्रकार की बहुत बातें होती हैं जो यहां पर नहीं ली जातीं इस मैशन के खत्म होते-होते। न तो आप कालिंग अटेंशन मन्जूर करते हैं विदेश मंत्रालय पर या विदेशी बातों पर और न बहस करते हैं। इस पर सरकार विचार करे कि क्यों फारेन अफेयर्स, न्यूक्लियर पालिसी से हम को विचार करने पर दूर रखा जाता है। मेरा कालिंग अटेंशन आपके पास है वह मन्जूर कर लीजिए। इन बातों पर सरकार विचार करे और अगले सप्ताह की सूची में इनको लाने की कोशिश करें।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS—contd.

श्री घन श्याम सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, मैं कल चर्चा कर रहा था कि हमारे विरोधी दल के